[2017] 12 S.C.R. 913

रवि सिन्हा और अन्य

बनाम

झारखंड राज्य

(क्रिमिनल अपील संख्या 1561 of 2008)

5 अक्टूबर 2017,

[न्यायमूर्ति जे. के. सिकरी और अशोक भूषण]

क्रिमिनल लॉ संशोधन अध्यादेश, 1944:

धारा 12 और 13 – अपीलकर्ता के पिता – एक सार्वजनिक सेवक – पर विभिन्न आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए। अपीलकर्ता खुद भी कई मामलों में शामिल थे। आरोपी व्यक्तियों ने एक साजिश के तहत राज्य सरकार को कई सौ करोड़ रुपये की ठगी की। 1944 के अध्यादेश के तहत कार्रवाई की गई। राज्य द्वारा संपत्तियों की अटैचमेंट की गई। बाद में अटैचमेंट आदेश को अंतिम रूप दे दिया गया। अपीलकर्ताओं की ओर से दायर अपील को हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। – अपील पर निर्णय: अपीलकर्ता के पिता के खिलाफ अभियोजन उनके निधन के बाद जारी नहीं रह सकता था और उन पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे मृत हैं। हालांकि, जिन संपत्तियों की पहले से अटैचमेंट की गई थी, वे अपीलकर्ता के हाथ में आ गईं क्योंकि वे एक कानूनी प्रतिनिधि हैं, जिन्हें एक फॉडर घोटाले में दोषी ठहराया गया है और एक अन्य मामले में परीक्षण का सामना कर रहे हैं। इस प्रकार, अटैचमेंट आदेश को अंतिम रूप देने में कोई दोष नहीं है। इसके अलावा, किसी दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील पहले से हाई कोर्ट में लंबित है और एक आपराधिक मामले में, आरोपियों के खिलाफ परीक्षण चल रहा है जिसमें धारा 12 और 13 का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि एक बार जब न्यायालय द्वारा आपराधिक मामले में निर्णय पारित किया जाता है और अगर अटैच की गई संपत्तियों के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिए जाते हैं, तो अटैच की गई संपत्तियों के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। अपीलकर्ता द्वारा अटैच की गई संपत्तियों की कीमत की गणना करने की आवश्यकता नहीं है - ये प्रश्न अपीलकर्ता द्वारा धारा 13 की कार्यवाही में या लंबित परीक्षण के दौरान धारा 12 का उपयोग करके उठाए जा सकते हैं। इस प्रकार, उच्च न्यायालय और न्यायिक आयुक्त द्वारा अटैचमेंट को अंतिम रूप देने के आदेश के खिलाफ इस कोर्ट की धारा 136 के तहत हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। – संविधान की धारा 136.

धारा 4 - कई आपराधिक मामले सीबीआई द्वारा विभिन्न आरोपियों के खिलाफ दर्ज किए गए। कथित धोखाधड़ी की राशि कई करोड़ रुपये की है। आरोप है कि एक आरोपी ने अपनी और परिवार की नाम पर चल और अचल संपत्तियाँ अर्जित कीं और संपत्ति में निवेश अपने स्रोत से नहीं किया। 1944 के अध्यादेश के तहत कार्रवाई की गई। – राज्य द्वारा संपत्तियों की अटैचमेंट की गई। – बाद में अटैचमेंट आदेश को अंतिम रूप दे दिया गया। –

अपील पर निर्णय: धारा 4 के अवलोकन से पता चलता है कि जो पैसे या अन्य संपत्ति संलग्न की गई थी, – उसके लिए यह शक्ति मौजूद है। – धारा 4 यह प्रदान करती है कि" यदि ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी संपत्ति या अन्य संपत्ति अटैच के लिए उपलब्ध नहीं है, तो जिला न्यायाधीश द्वारा उपयुक्त मूल्य की ऐसी अन्य संपत्ति संलग्न की जा सकती है।– " इस प्रकार, कई संपत्तियों को अटैच करने की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है ताकि उस राशि की देखरेख की जा सके जो कथित तौर पर डिफॉल्ट की गई थी।– इस प्रकार, 1955 में अर्जित की गई संपत्ति को अटैच किया जा सकता था। अपीलकर्ताओं की यह याचिका कि सबूतों की पुनः समीक्षा की जाए और यह तय किया जाए कि अटैच की गई संपत्तियाँ उनके खुद के वित्त से खरीदी गई थीं, धारा 136 के तहत नहीं देखी जा सकती। – भारत का संविधान – धारा 136

अपीलों को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा:

1. 1944 के क्रिमिनल लॉ संशोधन अध्यादेश के तहत आरोपी के खिलाफ कोई कार्यवाही उसके निधन के बाद नहीं की जा सकती और अभियोजन उसके निधन के बाद जारी नहीं रह सकता। यह विवाद की बात नहीं है कि अपीलकर्ता के पिता – एस.बी. – की मृत्यु के बाद अभियोजन जारी नहीं रह सकता था, और वास्तव में उनकी मृत्यु के बाद सीबीआई द्वारा चार्ज शीट दायर नहीं की गई। [पैरा 21] [925-A-B)

1.2 यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अपीलकर्ता-आर.एस. को फॉडर स्कैम मामले में दोषी ठहराया गया था और एक अन्य मामले में परीक्षण चल रहा है। आर.एस. के दोषी ठहराए जाने और एक अन्य मामले में परीक्षण जारी रहने के आदेश के साथ अटैचमेंट आदेश को अंतिम रूप देना गलत नहीं हो सकता। यह सच है कि एस.बी. के खिलाफ अभियोजन उनके निधन के बाद जारी नहीं रह सकता और एस.बी. पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे मृत हैं। हालांकि, जिन संपत्तियों की पहले से अटैचमेंट की गई थी, वे अपीलकर्ता आर.एस. के हाथ में आ गई हैं, जो एक कानूनी प्रतिनिधि हैं और फॉडर स्कैम मामले में दोषी ठहराए गए हैं और एक अन्य मामले में परीक्षण का सामना कर रहे हैं। इस मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि इस कोर्ट को अनुच्छेद 136 के तहत उच्च न्यायालय और न्यायिक आयुक्त के अटैचमेंट आदेश को अंतिम रूप देने के आदेश में हस्तक्षेप करना चाहिए। [पैरा 23] [926-A-D]

1.3 धारा 12(1) के अवलोकन से पता चलता है कि जब किसी आपराधिक परीक्षण में अदालत को बताया जाता है कि संपत्ति की अटैचमेंट का आदेश पहले से पारित किया जा चुका है, तो अदालत यदि आरोपी को दोषी ठहराती है, तो आरोपी द्वारा अपराध के माध्यम से अर्जित राशि या अन्य संपत्तियों के मूल्य के संबंध में एक निष्कर्ष दर्ज करना चाहिए। इस प्रकार, धारा 12(1) का उपयोग निर्णय पारित करने से पहले किया जाना चाहिए और अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संपत्ति की अटैचमेंट का आदेश पारित किया गया है। [पैरा 25] [929-B-C]

1.4 इस मामले में दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ 12.06.2008 को अपील पहले से हाई कोर्ट में लंबित है। इस प्रकार, आपराधिक कार्यवाही अभी समाप्त नहीं हुई है। इसके अलावा, एक आपराधिक मामले में, आरोपी के खिलाफ परीक्षण चल रहा है जिसमें धारा 12 और 13 का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि एक बार जब न्यायालय द्वारा आपराधिक मामले में निर्णय पारित किया जाता है और यदि अटैच की गई संपत्तियों के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिए जाते हैं, तो अटैच की गई संपत्तियों के संबंध में कोई आदेश नहीं पारित

किया जा सकता। धारा 13 अटैच की गई संपत्तियों से निपटने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करती है। अपीलकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि यदि आर.एस. के खिलाफ आरोप स्वीकार कर लिए जाएं, तो आरोप केवल 9.75 लाख रुपये और 2.95 लाख रुपये तक सीमित हैं और जब आरोप केवल उपर्युक्त राशि तक हैं, तो संपत्तियों को अटैच में रखने का कोई औचित्य नहीं है और इसके अलावा जमानत आदेश में, अपीलकर्ता ने पहले ही उपर्युक्त राशि प्राप्त कर ली है। यह देखा गया कि आर.एस. के खिलाफ एक और परीक्षण लंबित है। यह आवश्यक नहीं है कि आर.एस. द्वारा दुरुपयोग की गई राशि की मात्रा और अटैच की गई संपत्तियों के मूल्य की गणना की जाए। ये प्रश्न अपीलकर्ता आर.एस. द्वारा धारा 13 की कार्यवाही में या लंबित परीक्षण के दौरान धारा 12 का उपयोग करके उठाए जा सकते हैं। चूंकि यह कोर्ट केवल इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि अटैचमेंट आदेश को अंतिम रूप देना सही था या नहीं, और इस सबमिशन पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार, झारखंड हाई कोर्ट द्वारा न्यायिक आयुक्त के आदेश को अंतिम रूप देने के खिलाफ अपील को खारिज करने का आदेश इस कोर्ट के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 27] [930-D-H; 931-A-B]

1.5 पहले अंतरिम अटैचमेंट आदेशों को न्यायिक आयुक्त द्वारा अंतिम रूप दिया गया था, जिन आदेशों को उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया और मामले को पुनः विचार के लिए भेजा। पुनः विचार के बाद, अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए कारणों पर विचार किया गया, जिसे न्यायिक आयुक्त ने विस्तार से देखा। न्यायिक आयुक्त ने 13.10.2004 के आदेश में उन विभिन्न साक्ष्यों का उल्लेख किया, जो संपत्तियों के संबंध में पेश किए गए थे, जिसमें मौखिक साक्ष्य भी शामिल थे। तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, न्यायिक आयुक्त ने अटैचमेंट को अंतिम रूप देने के लिए मामले को उपयुक्त पाया। उच्च न्यायालय ने इस आदेश की पुष्टि की। अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा 1955 में खरीदी गई संपत्ति के बारे में प्रस्तुत किए गए तर्कों के संबंध में, राज्य के वकील ने कहा कि संपत्ति को अटैच करने की शक्ति केवल उन संपत्तियों तक सीमित नहीं है, जो गलत तरीके से अर्जित धन से खरीदी गई हैं, बल्कि किसी भी दुरुपयोग की गई संपत्ति को भी अटैच किया जा सकता है। धारा 4 का अवलोकन करने पर पता चलता है कि पैसे या अन्य संपत्तियों को अटैच करने की शक्ति मौजूद है। इसके अतिरिक्त, धारा यह प्रदान करती है कि "यदि ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा पैसा या अन्य संपत्ति अटैच करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की किसी अन्य संपत्ति को उसकी मूल्य के अनुसार अटैच किया जा सकता है..." इस प्रकार, शक्ति केवल एक संपत्ति तक सीमित नहीं है और कई संपत्तियों को अटैच करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इसलिए, 1955 में अर्जित संपत्ति को अटैच नहीं किया जा सकता, ऐसा तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस मामले में अपीलकर्ता मूल रूप से साक्ष्यों की पुनः समीक्षा करने और रिकॉर्ड करने की मांग कर रहे हैं कि अटैच की गई संपत्तियाँ उनके अपने वित्त से खरीदी गई थीं; जो कि अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 29, 30] [931-E-H; 932-A-E]

बिहार राज्य एवं अन्य. बनाम रांची जिला समता पार्टी और अन्य., (1996) 3 सेकंड 682: [1996) 3 एससीआर 663; *यू. सुभद्रम्मा एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य,* (2016) 7 एससीसी 797: [2016) 3 एससीआर 469; *झारखंड राज्य बनाम लालू प्रसाद यादव* (2017) 8 एससीसी 1 [2017) 3 एससीआर 630 - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

[1996) 3 SCR 663	**उल्लेखित**	**पैरा 3**
[2016) 3 SCR 469	**उल्लेखित**	**पैरा 13**
[2017) 3 SCR 630	**उल्लेखित**	**पैरा 16**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: अपराध अपील संख्या 1561 का 2008।

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के आदेश और निर्णय दिनांक 21.06.2007 से Cr. अपील संख्या 307 का 2001

साथ में

Crl. A. Nos. 1521, 1542-1543 और 1558-1559 का 2008

अपीलकर्ताओं के लिए: के. वी. विश्वनाथन, गुरु कृष्ण कुमार, सीनियर एडवोकेट्स, अमित पवन, अभिषेक अमृतांशु, हसन जुबैर वारिस, अक्षय सिन्हा, अक्षत श्रीवास्तव, मुकुंद राव अंगारा, सुश्री व्रिंदा भंडारी, आनंद नंदन, उज्जवल जैन, प्रणय जैन, डी. एन. गोबुर्धन, वकील।

प्रतिकूल पक्ष के लिए: के.के. वेणुगोपाल, एजी, विभा दत्ता माखिजा, सीनियर एडवोकेट, सुश्री रंजन नारायण, आर. बालासुब्रमणियन, प्रभास बजाज, अक्षय अमृतांशु, सुश्री आर्टी शर्मा, मुकेश कुमार मारोरिया, सुश्री दिशा वैष, अंकुर तलवार, हरिश वैद्यनाथन शंकर, सुश्री निष्ठा मोहनदास, बी. कृष्णा प्रसाद, अनिल के. झा, वकील।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण द्वारा अदालत का निर्णय: 1. ये सभी अपीलें 1944 के आपराधिक कानून (संशोधन) आदेश के तहत की गई कार्यवाही से उत्पन्न हुई हैं, जिसके तहत राज्य की ओर से दायर एक आवेदन पर कुछ संपत्तियों को अटैच किया गया था, जो बाद में स्थायी कर दी गई थीं। उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई आपराधिक अपीलें खारिज कर दी गईं, जिसके परिणामस्वरूप ये आपराधिक अपीलें दायर की गईं। आपराधिक अपील संख्या 1561 का 2008 और आपराधिक अपील संख्या 1521 का 2008 झारखंड उच्च न्यायालय के 21.06.2007 के सामान्य निर्णय के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई दो आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया।

2. आपराधिक अपील संख्या 1542-1543 का 2008 और आपराधिक अपील संख्या 1558-1559 का 2008 झारखंड उच्च न्यायालय के 21.06.2007 के सामान्य निर्णय के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई दो आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया गया।

आपराधिक अपील संख्या 1561 का 2008 और आपराधिक अपील संख्या 1521 का 2008 के तथ्य

3. इस अदालत ने 19.03.1996 को ***राज्य बिहार और अन्य बनाम रांची जिला समानता पार्टी और अन्य, (1996) 3 SCC 682*** में अपने आदेश के माध्यम से सार्वजनिक धन की बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, धोखाधड़ी और खातों की जालसाजी की एक घटना को सौंपा, जो कि बिहार राज्य के पशुपालन विभाग में लगभग 500 करोड़ रुपये की राशि के आसपास प्रकाश में आई थी। शिक्षा, सहकारिता और मत्स्य विभागों में भी ऐसी ही स्थिति थी। सभी वकीलों

ने इस मामले में सहमति जताई कि गहन जांच की आवश्यकता है। एकमात्र विवाद यह था कि क्या उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके राज्य पुलिस से जांच को हटाकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप सकता है।

4. संक्षेप में आरोप था कि एक बड़ी संख्या में आरोपियों ने साजिश के तहत बिहार सरकार (अब झारखंड) को 1990 से 1994 की अवधि के दौरान कई सौ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की, जिसमें फर्जी आवंटन पत्रों के आधार पर दवाइयाँ खरीदी गईं। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा फर्जी आपूर्तियाँ दिखाई गईं और फर्जी आवंटन आदेशों के आधार पर पैसे निकाले गए और उन पर आरोपियों, आपूर्तिकर्ताओं, सार्वजनिक कर्मचारियों और अन्य लोगों द्वारा दुरुपयोग किया गया। धारा 120B, 409, 420, 467, 468, 471 और 472 के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(c) & (d) के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए।

5. एक डॉ. एस.बी. सिन्हा, जो एक सार्वजनिक कर्मचारी थे, 41 आपराधिक मामलों में शामिल पाए गए। डॉ. एस.बी. सिन्हा, रवि सिन्हा के पिता थे, जो अपीलकर्ता संख्या 1 हैं, अपीलकर्ता संख्या 2 डॉ. एस.बी. सिन्हा के भतीजे हैं, अपीलकर्ता संख्या 3 डॉ. एस.बी. सिन्हा की पत्नी हैं और अपीलकर्ता संख्या 4 रवि सिन्हा की पत्नी हैं। राज्य बिहार ने न्यायिक आयुक्त, रांची के समक्ष धारा 3 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें डॉ. एस.बी. सिन्हा को प्रतिवादी संख्या 1, अपीलकर्ता संख्या 1 रवि सिन्हा को प्रतिवादी संख्या 2, अपीलकर्ता संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 4, अपीलकर्ता संख्या 3 को प्रतिवादी संख्या 5 और अपीलकर्ता संख्या 4 को प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में दर्शाया। आवेदन में उल्लेख किया गया कि सीबीआई द्वारा की गई जांच में पाया गया कि डॉ. एस.बी. सिन्हा 41 मामलों में शामिल थे और साजिश के परिणामस्वरूप बिहार सरकार को 600 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा।

6. एक आवेदन RC No.31(A)/96 में दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि आरोपी ने गलत तरीके से खुद को लाभ पहुंचाकर पैसे का दुरुपयोग किया और पैसे का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न संपत्तियों की प्राप्ति में खर्च किया गया। डॉ. एस.बी. सिन्हा और अन्य प्रतिवादियों के पास मौजूद संपत्तियों का विवरण परिशिष्ट-II में उल्लेखित किया गया। उस आवेदन में यह भी कहा गया कि आशंका है कि डॉ. एस.बी. सिन्हा, उनकी पत्नी, बच्चे और अन्य प्रतिवादी जांच के दौरान राशि निकालकर संपत्तियों को नष्ट कर देंगे, जो एक उन्नत अवस्था में है। उक्त आवेदन के आधार पर, न्यायिक आयुक्त, रांची द्वारा 30.08.1996 को एक आदेश पारित किया गया, जिसमें परिशिष्ट-II में विस्तृत संपत्तियों की अस्थायी अटैचमेंट की अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त, यह निर्देशित किया गया कि प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाए कि अस्थायी अटैचमेंट आदेश को स्थायी क्यों नहीं किया जाए। शो-कॉज का उत्तर 21.02.1997 को प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 और 5 द्वारा और 26.11.1998/08.12.1998 को प्रतिवादी संख्या 2 और 6 द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादियों ने न्यायिक आयुक्त, रांची की अधिकारिता को भी चुनौती दी। डॉ. एस.बी. सिन्हा का निधन 25.10.1999 को हुआ। न्यायिक आयुक्त ने शो-कॉज के समर्थन में सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया।

7. 26.03.2001 को, सीबीआई द्वारा एक याचिका दायर की गई जिसमें अस्थायी अटैचमेंट को स्थायी करने की प्रार्थना की गई। आवेदन के प्रतिवादी संख्या 2 से 6 ने न्यायिक आयुक्त, रांची के समक्ष कार्यवाही में भाग नहीं लिया। अप्रैल 1999 के बाद, न्यायिक आयुक्त द्वारा कई तिथियाँ निर्धारित की गईं जिनमें प्रतिवादियों को सबूत पेश

करने के लिए कई अवसर दिए गए। चूंकि इन अवसरों का उपयोग प्रतिवादियों द्वारा नहीं किया गया, न्यायिक आयुक्त ने 03.05.2001 को संपत्तियों की अस्थायी अटैचमेंट को स्थायी कर दिया। धारा 9(2) के तहत एक याचिका दायर की गई जिसमें एक रिसीवर नियुक्त करने की प्रार्थना की गई। न्यायिक आयुक्त ने 12.06.2001 को सीबीआई को सक्षम व्यक्तियों के नाम सुझाने का आदेश दिया। आदेशों 03.05.2001 और 12.06.2001 से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील संख्या 307 और 310 का दायर किया। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 21.06.2007 को आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया। इस निर्णय से असंतुष्ट होकर, आपराधिक अपील संख्या 1561 और 1521 का 2008 दायर की गई।

आपक आपराधिक अपील संख्या 1542-1543 और 1558-1559 का 2008

8. सीबीआई द्वारा विभिन्न आरोपियों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिसमें एक विजय कुमार मलिक भी शामिल था। विजय कुमार मलिक R.C. केस संख्या 28(A)/96, R.C. केस संख्या 32(A)/96 और R.C. केस संख्या 33(A)/96 में भी आरोपी था। इन तीन मामलों में धोखाधड़ी की कथित राशि 24,69,60,090 रुपये बताई गई थी जैसा कि पहले सूचना रिपोर्ट में दर्ज किया गया था। बिहार राज्य द्वारा विजय कुमार मलिक (ओ. पी. नंबर 1 के रूप में), श्रीमती कोमल मलिक (ओ. पी. नंबर 2 के रूप में) और संदीप मलिक और अन्य तीन व्यक्तियों के खिलाफ न्यायिक आयुक्त, रांची के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया। आवेदन में कहा गया कि जांच के दौरान पता चला कि विजय कुमार मलिक तीन मामलों में शामिल है जिनमें प्राइम फेसी धोखाधड़ी की राशि 24,69,60,090 रुपये है। इसके अतिरिक्त, यह आरोप लगाया गया कि विजय कुमार मलिक ने अपने नाम, पत्नी और बच्चों और अन्य लोगों के नाम पर विभिन्न स्थानों पर बड़ी मात्रा में चल और अचल संपत्तियाँ प्राप्त की हैं। परिशिष्ट-II में संपत्तियों का विवरण और विवरण दिया गया। यह भी कहा गया कि ओ. पी. नंबर 1 और अन्य ने अपनी स्वयं की आय के स्रोत से संपत्तियों में निवेश नहीं किया है। आवेदन में संपत्तियों की अस्थायी अटैचमेंट के लिए आदेश जारी करने की प्रार्थना की गई। 30.08.1996 को न्यायिक आयुक्त ने परिशिष्ट-II में दी गई जानकारी के अनुसार संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच करने का आदेश पारित किया। अस्थायी अटैचमेंट आदेश को 27.04.2001 को स्थायी किया गया और 12.07.2001 को एक और आदेश पारित किया गया जिसमें सीबीआई को रिसीवर की नियुक्ति के लिए नाम सुझाने का निर्देश दिया गया।

9. आवेदन के प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 4 ने झारखंड उच्च न्यायालय में आपराधिक अपीलें दायर कीं। झारखंड उच्च न्यायालय ने 26.03.2003 को न्यायिक आयुक्त द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया और न्यायिक आयुक्त को पक्षों को सुनने के बाद एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया। शो-कॉज न्यायिक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायिक आयुक्त ने शो-कॉज पर विचार करने के बाद 13.10.2004 को एक विस्तृत आदेश पारित किया, जिसमें अस्थायी आदेश को स्थायी कर दिया गया। 18.10.2004 को, अटैच की गई संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए रिसीवर नियुक्त करने का निर्देश दिया गया। बाद में 14.12.2004 को, डिप्टी कमिश्नर, रांची को रिसीवर नियुक्त किया गया।

10. आदेश 13.10.2004, 18.10.2004 और 14.12.2004 के खिलाफ आपराधिक अपीलें दायर की गईं, जो झारखंड उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील संख्या 1931 of 2004 और 694 of 2005 के रूप में थीं। झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 21.06.2007 को दोनों अपीलों को खारिज कर दिया। इस निर्णय से असंतुष्ट होकर,

संदीप मलिक ने आपराधिक अपील संख्या 1542-1543 of 2008 और कमल मलिक ने आपराधिक अपील संख्या 1558-1559 of 2008 दायर की।

11. हमने इन आपराधिक अपीलों में अपीलकर्ताओं के लिए उपस्थित अधिवक्ताओं के साथ-साथ झारखंड राज्य के लिए उपस्थित अधिवक्ताओं को सुना।

12. सबसे पहले हम आपराधिक अपील संख्या 1561 of 2008 और 1521 of 2008 को उठाते हैं, जो रवि सिन्हा और अन्य द्वारा दायर की गई हैं। श्री के. वी. विश्वनाथन, जो अपीलकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ने अपीलों के समर्थन में विभिन्न प्रस्तुतियाँ दी हैं। श्री के. वी. विश्वनाथन द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों में से एक यह है कि डॉ. एस.बी. सिन्हा, जो कथित रूप से साजिश का मास्टरमाइंड था, 25.10.1999 को मृत्यु हो गई, और यह तथ्य न्यायिक आयुक्त को सूचित किया गया था, इसलिए अटैचमेंट को जारी रखने और 03.05.2001 को अटैचमेंट आदेश को स्थायी बनाने का कोई कारण नहीं था। उनका कहना है कि डॉ. एस.बी. सिन्हा की मृत्यु के कारण उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो गई है। डॉ. एस.बी. सिन्हा को अब दोषी नहीं ठहराया जा सकता था और अटैचमेंट आदेश को वापस लिया जाना चाहिए था।

13. वरिष्ठ अधिवक्ता ने ***यू. सुभद्रम्मा एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2016) 7 SCC 797*** के निर्णय पर भरोसा किया। उनका कहना है कि एक आरोपी की मृत्यु के कारण न तो कोई दोष निर्धारित किया जा सकता है और न ही किसी प्रकार की सजा आदेशित की जा सकती है, और संपत्तियों के अटैचमेंट आदेश को वापस लिया जाना चाहिए था, और न्यायिक आयुक्त ने आदेश को स्थायी बनाने में गलती की। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं पर केवल नाम उधार देने का आरोप था और रवि सिन्हा के अलावा अन्य तीन अपीलकर्ता चारा घोटाले के मामले में शामिल नहीं थे। किसी भी स्थिति में, अटैचमेंट केवल डॉ. एस.बी. सिन्हा की संपत्तियों के संबंध में हो सकता था और वर्तमान अपीलकर्ताओं की संपत्तियों को अटैच नहीं किया जा सकता था। रवि सिन्हा चार मामलों में आरोपी है, जिनमें से एक में उसे बरी किया गया है और एक अन्य मामले में उसे ट्रायल के लिए नहीं भेजा गया है। एक मामले, यानी RC No. 39/1996 में अपील पहले ही उच्च न्यायालय में दायर की जा चुकी है और केस, यानी R.C. No. 68/1996 ट्रायल कोर्ट में लंबित है। उनका यह भी कहना है कि RC No. 39/1996 और RC No. 68/1996 में कथित रूप से दुरुपयोग की गई राशि सुरक्षित है क्योंकि इसे जमानत देने के आदेश के अनुसार ट्रायल कोर्ट में जमा किया गया था।

14. यह भी कहा गया कि सीबीआई ने RC No. 39/1996 में दोषसिद्धि के चरण में 1944 के अध्यादेश की धारा 12 के तहत आदेश नहीं मांगे, अब ऐसा नहीं कर सकता। धारा 12 का चरण आ चुका है और चला गया है, अब अटैच की गई संपत्तियों के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

15. श्री के.के. वेणुगोपाल, जो महाधिवक्ता हैं, ने अपीलकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता की प्रस्तुतियों का खंडन करते हुए कहा कि अटैचमेंट का आदेश और अटैचमेंट को स्थायी बनाने का आदेश कानूनी अनुसार है। उन्होंने कहा कि चारा घोटाले में, जो दवाइयों की आपूर्ति से संबंधित है और जिसमें 600 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई है, आरोपी एक बड़े साजिश का हिस्सा हैं। रवि सिन्हा को पहले ही 12.06.2008 को RC No. 39(A) of 1996 (Spl. No. 41 of 1996) में दोषी ठहराया गया है, यह साबित हो गया है कि उसने अपराध किया है। विभिन्न अपराधों के लिए सख्त कारावास की सजा सहित दंड लगाया गया है। इस स्तर पर जहां एक बड़ा साजिश रचा गया और बड़ी संख्या में आरोपी दोषी ठहराए गए हैं और/या अभी भी ट्रायल का सामना कर रहे हैं, संपत्तियों की अटैचमेंट को वापस

नहीं लिया जा सकता। हालांकि डॉ. एस.बी. सिन्हा की मृत्यु 1999 में हो गई, अटैच की गई संपत्तियों को जारी नहीं किया जा सकता। उनके एक कानूनी उत्तराधिकारी भी सरकारी धन को दुरुपयोग करने के इसी बड़े साजिश में आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं।

16. श्री के.के. वेणुगोपाल ने आगे कहा कि यह तथ्य कि चार्जशीट में श्री रवि सिन्हा के खिलाफ आरोपों में एक विशिष्ट राशि का उल्लेख किया गया है, यह नहीं कह सकता कि जब उक्त राशि का उल्लेख किया गया है, तो पहले से अटैच की गई संपत्तियों को वापस ले लिया जाना चाहिए। क्योंकि संपत्तियां बड़े साजिश के तहत प्राप्त की गई थीं और छोटी साजिश बड़ी साजिश का हिस्सा थी। श्री वेणुगोपाल ने इस कोर्ट के निर्णय ***झारखंड राज्य बनाम. लालू प्रसाद यादव, (2017) 8 SCC 1*** का भी उल्लेख किया। श्री के.के. वेणुगोपाल ने अध्यादेश की धारा 12 और 13 के संबंध में प्रस्तुतियों का उत्तर देते हुए कहा कि धारा 12 और 13 के तहत कार्यवाही स्वतंत्र होती हैं और केवल इसलिए कि रवि सिन्हा के खिलाफ दोषसिद्धि के समय संपत्तियों का उल्लेख नहीं किया गया, इसका यह अर्थ नहीं है कि अध्यादेश की धारा 13 के तहत आदेश पारित नहीं किया जा सकता। आपराधिक कार्यवाही पूरी होने के बाद, धारा 13 के तहत आदेश पारित किया जा सकता है।

<u>आपराधिक अपील संख्या 1542-1543 of 2008 और 1558-1559 of 2008 में प्रस्तुतियाँ</u>

17. उपरोक्त आपराधिक अपीलों में अपीलकर्ता के लिए उपस्थित अधिवक्ता का कहना है कि ये अपीलें रवि सिन्हा के मामले से पूरी तरह से अलग मुद्दों से संबंधित हैं। ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय ने विभिन्न सामग्री जैसे कि आयकर रिटर्न, संपत्ति कर रिटर्न, बिजली के बिल, घर के कर रसीदें, बैंक ड्राफ्ट आदि पर विचार नहीं किया, जो अपीलकर्ताओं की स्वतंत्र स्थिति/आय के स्रोतों को स्पष्ट रूप से स्थापित करती हैं। उच्च न्यायालय ने केवल ट्रायल कोर्ट के आदेश की पुष्टि की बिना सामग्री पर विचार किए। स्ल. नं. 3 के संपत्ति, यानी कश्मीरी गेट संपत्ति की अटैचमेंट के लिए कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि यह संपत्ति 1955 में संदीप मलिक के नाम पर प्राप्त की गई थी। कश्मीरी गेट, दिल्ली की संपत्ति संख्या 158, गली बगिचेवाली को 1955 में सार्वजनिक नीलामी में खरीदी गई थी। इंजीनियर्स एन्क्लेव, नई दिल्ली की संपत्ति, जिसमें संदीप मलिक सह-मालिक हैं, 1991 में खरीदी गई थी, यानी कथित घोटाले से बहुत पहले।

18. झारखंड राज्य के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने उपरोक्त प्रस्तुतियों का खंडन करते हुए कहा कि राज्य द्वारा दायर आवेदन में स्पष्ट रूप से आरोपित किया गया था कि संपत्तियां विजय कुमार मलिक द्वारा उनके नाम और उनके रिश्तेदारों के नाम पर अवैध धन से खरीदी गईं। यह भी कहा गया कि संपत्तियों की कीमत केवल लगभग 25 लाख रुपये थी जबकि आरोपित दुरुपयोग की राशि एक करोड़ से अधिक थी, इसलिए अन्य संपत्तियों की अटैचमेंट भी अध्यादेश, 1944 के प्रावधानों के तहत वैध है।

19. हमने पक्षों के अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों पर विचार किया है और रिकॉर्ड की समीक्षा की है।

20. सबसे पहले हम श्री के. वी. विश्वनाथन द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करते हैं। श्री के. वी. विश्वनाथन की मुख्य प्रस्तुति यह है कि डॉ. एस.बी. सिन्हा की मृत्यु 25.10.1999 को हो गई थी, इसलिए संपत्तियों की अटैचमेंट को वापस ले लिया जाना चाहिए था क्योंकि आरोपी की मृत्यु के बाद न तो कोई दोषसिद्धि आदेश पारित किया जा सकता है और न ही किसी प्रकार का दोष घोषित किया जा सकता है। उन्होंने इस कोर्ट के निर्णय ***यू. सुभद्रम्मा एवं***

अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (उपर्युक्त) पर भरोसा किया। इस कोर्ट ने उक्त मामले में 1944 के अध्यादेश के प्रावधानों पर विचार किया। आरोपी की मृत्यु के बाद संपत्तियों की अटैचमेंट की गई और उसके कई वर्षों बाद दोषसिद्धि की गई। इस कोर्ट ने कहा कि आरोपी की मृत्यु के बाद अटैचमेंट के लिए कोई आवेदन नहीं किया जा सकता और मृत्यु के बाद दोषसिद्धि को अमान्य माना जाएगा। निर्णय के पैरा 12 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

> "12. वास्तव में, हम पाते हैं कि विद्वान जिला जज को अटैचमेंट कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने का अधिकार नहीं था क्योंकि अटैचमेंट कार्यवाही राज्य द्वारा रामचंद्रैया के खिलाफ धारा 3 के तहत शुरू की गई थी, जो वास्तव में मृत था। धारा 3 की कल्पना करती है कि ऐसी आवेदन जिला न्यायाधीश के समक्ष की जानी चाहिए जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है या व्यवसाय करता है, संपत्ति के संबंध में जो राज्य सरकार को विश्वास हो कि उक्त व्यक्ति ने अपराधों के माध्यम से प्राप्त की है। इसलिए, यह अविश्वसनीय है कि एक मृत व्यक्ति के संबंध में ऐसा आवेदन किया जा सकता है जो स्पष्ट रूप से सामान्यतः निवासी या कहीं भी व्यवसाय नहीं कर सकता। कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जो आरोपी की मृत्यु के बाद अभियोजन की निरंतरता की अनुमति देता है। हमें रिकॉर्ड करना होगा कि नीचे की अदालतों की कार्यवाही और निर्णय परेशान करने वाले हैं, कम से कम। पहले स्थान पर, हालांकि आरोपी की मृत्यु हो गई थी, ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल को जारी रखा और उसकी मृत्यु के दो साल बाद दोषसिद्धि रिकॉर्ड की। फिर, इस अमान्य दोषसिद्धि का उपयोग उसके संपत्तियों की अटैचमेंट करने के लिए सत्र न्यायालय के समक्ष किया गया। चौंकाने वाला है, सभी आवेदन सफल हुए, अटैचमेंट को स्थायी किया गया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उच्च न्यायालय ने अटैचमेंट को मान्यता दी।

21. इसमें कोई विवाद नहीं है कि 1944 के अध्यादेश के तहत किसी आरोपी के खिलाफ कार्यवाही उसकी मृत्यु के बाद नहीं की जा सकती और अभियोजन उसके मृत्यु के बाद जारी नहीं रह सकता। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि डॉ. एस.बी. सिन्हा की मृत्यु के बाद उनके खिलाफ कोई अभियोजन जारी नहीं रह सकता था। वास्तव में, उनकी मृत्यु की सूचना मिलने के बाद, सी.बी.आई. ने डॉ. एस.बी. सिन्हा के खिलाफ चार्ज शीट भी प्रस्तुत नहीं की।

22. वर्तमान मामले में एक तथ्य है जो इसे ***यू. सुभद्रम्मा एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (उपर्युक्त)*** मामले से अलग बनाता है अर्थात वर्तमान मामले में, डॉ. एस.बी. सिन्हा के पुत्र रवि सिन्हा स्वयं कई मामलों में आरोपी हैं। एक मामले में उन्हें पहले ही दोषी ठहराया गया था और दंडित किया गया था। एक अन्य मामले में, जो समान फॉडर स्कैम से संबंधित है, अर्थात् R.C. No. 36/1996, का ट्रायल चल रहा है। R.C. Case No. 39/1996 में रवि सिन्हा पर आरोप था कि उन्होंने भुगतान प्राप्त किया लेकिन दवा की आपूर्ति नहीं की जिसकी कीमत 9.75 लाख रुपये थी। रवि सिन्हा ने अपने अपील No. 1561 of 2008 में एक प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल किया और पारा 16 में निम्नलिखित उल्लेख किया:

> "इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि रवि सिन्हा के खिलाफ चार मामलों में से एक में उन्हें बरी कर दिया गया है और दूसरे में ट्रायल के लिए भेजा नहीं गया है। अन्य दो मामलों में से एक में ट्रायल चल रहा है और दूसरे में उन्हें दोषी ठहराया गया है लेकिन उनकी अपील उच्च न्यायालय में लंबित है। पहले दो मामलों के

बारे में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अन्य दोनों मामलों में, यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो भी रवि सिन्हा द्वारा कथित रूप से दुरुपयोग की गई राशि पहले ही ट्रायल कोर्ट में जमा की जा चुकी है। इसलिए रवि सिन्हा के खिलाफ अलग से अटैचमेंट कार्यवाही शुरू करने की कोई तर्कसंगतता नहीं है क्योंकि अध्यादेश के तहत अटैचमेंट कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य कथित दुरुपयोग की गई राशि को सुरक्षित करना है ताकि दोषसिद्धि की स्थिति में अटैच की गई संपत्तियों को जब्त और नष्ट किया जा सके ताकि दुरुपयोग की गई राशि की भरपाई की जा सके। इस कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सीबीआई ने रवि सिन्हा के खिलाफ अटैचमेंट कार्यवाही शुरू नहीं की है और नहीं कर सकती है, लेकिन इस मुद्दे को उठा रही है केवल अदालत को पूर्वाग्रहित करने के लिए।"

शून्य दिनांकित चार्ट की सच्ची प्रतिलिपि जिसमें विरुद्ध मामलों की स्थिति दी गई है रवि सिन्हा को इसके साथ संलग्नक-आर/11" अंकित किया गया है।

23. इस प्रकार यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि रवि सिन्हा को फॉडर स्कैम केस में दोषी ठहराया गया है और एक मामले में ट्रायल चल रहा है। रवि सिन्हा की दोषसिद्धि का आदेश और दूसरे मामले में ट्रायल चल रहा है, जिससे अटैचमेंट आदेश को स्थायी बनाना दोषपूर्ण नहीं हो सकता। यह सत्य है कि डॉ. एस.बी. सिन्हा के खिलाफ अभियोजन उनकी मृत्यु के बाद जारी नहीं रह सकता और उनके खिलाफ कोई दोष घोषित नहीं किया जा सकता। हालांकि, जो संपत्तियाँ पहले से अटैच की गई थीं, और जो रवि सिन्हा के पास आई हैं, जो एक कानूनी प्रतिनिधि के रूप में दोषी ठहराए गए हैं और एक अन्य मामले में ट्रायल का सामना कर रहे हैं, वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जिसमें हम अनुच्छेद 136 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर सकें। इसलिए, हम यह नहीं मानते कि इस मामले में अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप करना उचित है।

24. अब श्री विश्वनाथन द्वारा प्रस्तुत धारा 12 और 13 के बारे में प्रस्तुतियों पर विचार करना आवश्यक है। अध्यादेश की धारा 12 और 13 इस प्रकार हैं:

"12. अपराधी अदालतों को अनुसूचित अपराधों द्वारा प्राप्त संपत्ति का मूल्यांकन करना।

(1) जब किसी अपराधी परीक्षण के निर्णय से पहले यह अदालत को प्रस्तुत किया जाता है कि इस अध्यादेश के तहत संपत्ति की अटैचमेंट का आदेश पास किया गया है, तो अदालत यदि आरोपी को दोषी ठहराती है, तो वह यह रिकॉर्ड करेगी कि आरोपी ने अपराध के माध्यम से कितनी राशि या अन्य संपत्ति प्राप्त की है।

(2) यदि इस दोषसिद्धि के खिलाफ अपील या पुनरावलोकन कार्यवाही में अपीलीय या पुनरावलोकन अदालत दोषसिद्धि को निरस्त नहीं करती है, तो अपीलीय या पुनरावलोकन अदालत या तो इस खोज की पुष्टि करेगी या इसे उचित समझे जाने वाले तरीके से संशोधित करेगी।

(3) किसी ऐसी ट्रायल में जिस पर उपधारा (1) लागू होती है, यदि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील या पुनरावलोकन कार्यवाही में कोई दोषसिद्धि होती है, तो अपीलीय या पुनरावलोकन अदालत को उपधारा (1) के तहत की गई खोज रिकॉर्ड करनी होगी।

(4) जहां अभियुक्त को इस अध्यादेश की अनुसूची के आइटम । में निर्दिष्ट अपराध के अलावा किसी अन्य अनुसूचित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और जहां ऐसा प्रतीत होता है कि अपराध से अधिक की हानि हुई है उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट एक सरकार या स्थानीय प्राधिकारी इस खंड में निर्दिष्ट निष्कर्ष की राशि का संकेत देगा ऐसी प्रत्येक सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को हुई हानि।

(5) जहां आरोपी को एक या एक ही मुकदमे में दोषी ठहराया जाता है इस अध्यादेश की अनुसूची के आइटम । में निर्दिष्ट अधिक अपराध और किसी भी अन्य मद में निर्दिष्ट एक या अधिक अपराध उक्त अनुसूची, इस खंड में निर्दिष्ट निष्कर्ष इंगित करेगा दोनों वर्गों के माध्यम से अलग-अलग राशि प्राप्त की गई अपराध।

13. अपराध समाप्ति के बाद अटैच की गई संपत्ति का निपटान।

(1) जब किसी अनुसूचित अपराध की आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो जाती है, जिसके संबंध में इस अध्यादेश के तहत संपत्ति का अटैचमेंट आदेश या उसकी जगह सुरक्षा दी गई हो, तो राज्य सरकार या, जहां आवश्यक हो, केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि बिना किसी देरी के जिला न्यायाधीश को सूचित करेगा और जहां आपराधिक कार्यवाही किसी अदालत में की गई हो, वहां जिला न्यायाधीश को ट्रायल कोर्ट का निर्णय या आदेश की एक प्रति और अपीलीय या पुनरावलोकन अदालतों के आदेशों की प्रतियां प्रदान करेगा।

(2) यदि जिला न्यायाधीश को उपधारा (1) के तहत यह रिपोर्ट की जाती है कि आरोपित अनुसूचित अपराध की संज्ञान नहीं ली गई है या जहां आपराधिक अदालत का अंतिम निर्णय या आदेश बरी होने का है, तो जिला न्यायाधीश तुरंत उस अपराध के संबंध में किए गए किसी भी अटैचमेंट आदेश को रद्द कर देगा, या जहां अटैचमेंट की जगह सुरक्षा दी गई हो, वहां ऐसी सुरक्षा को लौटाने का आदेश देगा।

(3) जहां आपराधिक अदालत का अंतिम निर्णय या आदेश दोषसिद्धि का है, जिला न्यायाधीश आदेश देगा कि दोषी व्यक्ति की संपत्ति, जो इस अध्यादेश के तहत अटैच की गई थी या अटैचमेंट की जगह दी गई सुरक्षा से, वह राशि या मूल्य सरकार को जब्त किया जाएगा जैसा कि अंतिम निर्णय या आदेश में धारा 12 के अनुसार निर्धारित किया गया है कि दोषी व्यक्ति ने अपराध के माध्यम से प्राप्त किया है, साथ ही अटैचमेंट की लागत, जिसे जिला न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जहां आपराधिक अदालत का अंतिम निर्णय या आदेश दोषी व्यक्ति पर दंड का आदेश करता है (चाहे अकेले या किसी अन्य दंड के साथ), जिला न्यायाधीश आदेश दे सकता है, अन्य पुनर्प्राप्ति के तरीके को नुकसान पहुंचाए बिना, कि यह दंड अटैच की गई संपत्ति के अवशेष या सुरक्षा से वसूला जाएगा।

(4) जहां उपधारा (3) के तहत आदेशित जब्ती या वसूली की गई राशि दोषी व्यक्ति की अटैच की गई संपत्ति के मूल्य से अधिक है, और जहां दोषी व्यक्ति के किसी हस्तांतरणकर्ता की संपत्ति को धारा 6 के तहत अटैच किया गया है, जिला न्यायाधीश आदेश देगा कि उपधारा (3) के तहत आदेशित शेष राशि, साथ ही हस्तांतरणकर्ता की संपत्ति की अटैचमेंट की लागत, जो जिला न्यायाधीश द्वारा निर्धारित की जाएगी, सरकार से वसूली जाएगी। जिला न्यायाधीश आदेश दे सकता है, अन्य पुनर्प्राप्ति के तरीके को नुकसान

पहुंचाए बिना, कि उपधारा (3) के तहत कोई भी दंड या उसका कोई हिस्सा, जो इस उपधारा के तहत वसूला नहीं गया है, उसे हस्तांतरणकर्ता की अटैच की गई संपत्ति से या सुरक्षा से वसूला जाएगा।

(5) यदि किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में कोई संपत्ति अटैच की जाती है या सुरक्षा दी जाती है और उपधारा (3) और (4) के तहत आदेशों के प्रभावी होने के बाद भी जिला न्यायाधीश के पास रहती है, तो उस संपत्ति के संबंध में अटैचमेंट आदेश को तुरंत हटा दिया जाएगा या, जहां आवश्यक हो, सुरक्षा का शेष भाग लौटाया जाएगा, जिला न्यायाधीश के आदेशों के तहत।

(6) इस धारा के तहत किसी भी अनुसूचित अपराध के संबंध में आदेशित हर राशि, जो अनुक्रमांक । में निर्दिष्ट नहीं है, जिला न्यायाधीश द्वारा निर्धारित अटैचमेंट की लागत की कटौती के बाद, सरकार (जो उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सरकार है) या स्थानीय प्राधिकरण को जमा की जाएगी, जिसे अपराध ने हानि पहुंचाई है। यदि एक से अधिक ऐसी सरकारें या स्थानीय प्राधिकरण हैं, तो राशि की कटौती के बाद, इसे प्रत्येक द्वारा उठाई गई हानि के अनुपात में बांटा जाएगा।

25. धारा 12(1) की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि जब किसी भी आपराधिक परीक्षण में अदालत के समक्ष यह दर्शाया जाता है कि संपत्ति की जब्ती का आदेश पहले ही पारित किया जा चुका है, तो यदि अदालत आरोपी को दोषी ठहराती है, तो अदालत को यह निर्धारित करना होगा कि आरोपी ने अपराध के माध्यम से कितनी धनराशि या संपत्ति प्राप्त की है। इस प्रकार, धारा 12(1) को निर्णय सुनाए जाने से पहले लागू किया जाना चाहिए और अदालत को यह निर्धारित करने की जिम्मेदारी है <u>जब अदालत के समक्ष यह दर्शाया गया हो कि संपत्ति की जब्ती का आदेश पारित किया जा चुका है।</u>

26. माननीय अटॉर्नी जनरल ने हमें 12.06.2008 की तारीख का निर्णय प्रस्तुत किया है जिसमें ट्रायल कोर्ट ने रवि सिन्हा को दोषी ठहराया है। इस निर्णय की समीक्षा से यह स्पष्ट नहीं होता कि अदालत के समक्ष सीबीआई द्वारा यह दर्शाया गया कि कोई संपत्ति पहले ही जब्त की जा चुकी है। इस प्रकार, वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहां धारा 12(1) के तहत कोई आदेश पारित किया जाना था। श्री विश्वनाथन ने प्रस्तुत किया है कि एक बार धारा 12(1) का चरण समाप्त हो जाने के बाद, इसे बाद में लागू नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार, अब संपत्तियों के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता, इसलिए जब्ती की निरंतरता के लिए कोई औचित्य नहीं है। यह प्रश्न कि क्या संपत्तियों के संबंध में अभी भी कोई आदेश पारित किया जा सकता है, इसका उत्तर देना आवश्यक है। धारा 13, 1944 के अध्यादेश में बताया गया है कि आपराधिक प्रक्रिया के समाप्त होने पर जब्त की गई संपत्तियों का निपटान कैसे किया जाएगा। आपराधिक प्रक्रिया की समाप्ति की परिभाषा धारा 2(2) में दी गई है, जो निम्नलिखित है:

"2(2). इस अध्यादेश के उद्देश्य के लिए, आपराधिक प्रक्रिया की समाप्ति की तिथि मानी जाएगी:

(a) यदि ऐसी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए भेजी जाती है, चाहे उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र पर या अन्यथा, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस अपील में अंतिम आदेश पारित करने की तिथि; या

(b) यदि ऐसी प्रक्रिया उच्च न्यायालय में भेजी जाती है और आदेश पारित होते हैं और

(i) यदि उच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र की कोई याचिका दायर नहीं की जाती है, तो उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित करने की तिथि से नब्बे दिनों की समाप्ति के अगले दिन;

(ii) यदि उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र देने की याचिका को अस्वीकृत कर दिया है, तो प्रमाण पत्र की अस्वीकृति की तिथि से साठ दिनों की समाप्ति के अगले दिन;

(iii) यदि उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की जाती है, तो प्रमाण पत्र देने की तिथि से तीस दिनों की समाप्ति के अगले दिन;

या

(c) यदि ऐसी प्रक्रिया उच्च न्यायालय में नहीं भेजी जाती है, तो आपराधिक अदालत के अंतिम निर्णय या आदेश की तिथि से साठ दिनों की समाप्ति के अगले दिन।"

27. वर्तमान मामले में 12.06.2008 के आदेश के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में लंबित है जैसा कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार, आपराधिक प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, एक आपराधिक मामले में आरोपी के खिलाफ ट्रायल अभी भी चल रहा है जिसमें धारा 12 और 13 के प्रावधानों का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि एक बार जब अदालत द्वारा आपराधिक मामले में निर्णय पारित कर दिया गया और यदि जब्त संपत्तियों के संबंध में कोई निष्कर्ष रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो संपत्तियों के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। धारा 13 आपराधिक प्रक्रिया की समाप्ति के बाद जब्त की गई संपत्तियों को निपटाने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करती है। श्री विश्वनाथन ने यह भी प्रस्तुत किया है कि रवि सिन्हा के खिलाफ आरोपों को स्वीकार करते हुए भी, आरोप केवल 9.75 लाख रुपये और 2.95 लाख रुपये तक ही सीमित हैं। वे कहते हैं कि जब आरोप केवल दिए गए राशि तक सीमित हैं और जमानत के आदेश में अपीलकर्ता ने पहले ही उक्त राशि को सुरक्षित कर लिया है, तो संपत्तियों को जब्त में रखने के लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता। हमने पहले ही देखा है कि रवि सिन्हा के खिलाफ एक और ट्रायल लंबित है। यह आवश्यक नहीं है कि हम रवि सिन्हा द्वारा गलत तरीके से प्राप्त राशि की सीमा और जब्त संपत्तियों के मूल्य की गणना करें। ये प्रश्न अपीलकर्ता रवि सिन्हा द्वारा धारा 13 की प्रक्रिया में या लंबित ट्रायल के निर्णय के समय धारा 12, 1944 का उपयोग करके उठाए जा सकते हैं। हम केवल इस प्रश्न पर सीमित हैं कि क्या जब्ती आदेश को निराधारित किया जाना चाहिए था, और इसलिए इस प्रस्तुतिकरण को विस्तार से देखने या कोई राय व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है? हम इस प्रकार से विचार करते हैं कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जिसमें न्यायिक आयुक्त द्वारा पारित कुर्की आदेश को पूर्ण बनाने के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपीलों को खारिज किया गया था, के संबंध में हमारे अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

28. अब हम संदीप मलिक और कमल मलिक की आपराधिक अपीलों पर आते हैं। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई आपराधिक अपीलों को खारिज करते हुए अनुच्छेद 8 में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की हैं:

"13.10.2004 की विवादित आदेश की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि नीचे की अदालत ने मामले के प्रत्येक पहलू पर विचार किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि विपक्षी पार्टी-अपीलकर्ताओं ने यह साबित करने में

विफल रहे कि उन संपत्तियों को उनके अपने आय के स्रोत से खरीदी गई थीं। दूसरी ओर, नीचे की अदालत ने अभियोजन एजेंसी द्वारा एकत्रित की गई विभिन्न सामग्री का संदर्भ देते हुए यह दिखाया कि उन संपत्तियों को अपीलकर्ता संख्या 1, विजय कुमार मलिक, द्वारा बुरे पैसे से खरीदी गईं। इसमें कोई विवाद नहीं है कि अन्य अपीलकर्ता अपीलकर्ता संख्या 1, विजय कुमार मलिक, के करीबी संबंधी हैं, जिन्हें अंततः नीचे की अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है।"

29. जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, पहले अस्थायी जब्ती आदेशों को न्यायिक आयुक्त द्वारा अंतिम रूप दिया गया था, जिन आदेशों को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया और मामला वापस भेजा गया। रिमांड के बाद, अपीलकर्ताओं द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया, जिसे हमने न्यायिक आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विस्तृत रूप से विचार किया। न्यायिक आयुक्त ने 13.10.2004 के आदेश में रिकॉर्ड पर लाए गए विभिन्न साक्ष्यों का संदर्भ दिया है, जिसमें संपत्तियों के बारे में मौखिक साक्ष्य भी शामिल हैं, जैसे इंजीनियर्स एन्क्लेव, और 158, बगीचेवाली, कश्मीरी गेट, नई दिल्ली। कागजी किताब के पन्ने 76 से 81 तक का विस्तृत विचार किया गया है। तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार के बाद, न्यायिक आयुक्त ने जब्ती को अंतिम रूप देने के लिए इसे उपयुक्त पाया। उच्च न्यायालय ने 21.06.2007 की तारीख के अपने निर्णय के माध्यम से उपर्युक्त आदेश की पुष्टि की है। कश्मीरी गेट संपत्ति के संबंध में अपीलकर्ताओं के वकील की दलीलों के बारे में, जो 1955 में खरीदी गई थी, राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि संपत्ति को जब्त करने की शक्ति केवल बुरे पैसे से खरीदी गई संपत्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी आरोपी की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है जो कि अनुचित तरीके से प्राप्त की गई हो। 1944 के अध्यादेश की धारा 4 की समीक्षा से पता चलता है कि पैसे या अन्य संपत्ति को जब्त करने की शक्ति मौजूद है। इसके अलावा, धारा यह प्रदान करती है कि "यदि ऐसा पता चलता है कि ऐसी पैसे या अन्य संपत्ति उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी व्यक्ति की अन्य संपत्ति जिसका मूल्य जिला न्यायाधीश द्वारा उपयुक्त समझा जा सकता है..." इस प्रकार, शक्ति सीमित नहीं है और यह कई संपत्तियों को जब्त करने के लिए प्रयोग की जा सकती है ताकि कथित डिफॉल्ट की राशि की देखभाल की जा सके। वर्तमान मामले में, जब्ती को अंतिम रूप देने वाले आदेश में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:

"वर्तमान मामले में मुख्य आवेदन के परिशिष्ट-I में दिखाया गया है कि ओ.पी. संख्या 1 द्वारा ए.एस.डी. चाईबासा से प्राप्त राशि 1,49,41,000/- रुपये है। मुख्य आवेदन के परिशिष्ट-II में दिखाया गया है कि जब्त की गई संपत्तियों का मूल्य 25 लाख रुपये है जो कि कथित रूप से अनुशासित अपराधों के माध्यम से प्राप्त राशि से बहुत कम है..."

इस प्रकार, यह दलील कि 1955 में प्राप्त संपत्ति को जब्त नहीं किया जा सकता स्वीकार नहीं की जा सकती।

30. वर्तमान मामले में अपीलकर्ता हमें वास्तव में साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने और यह निष्कर्ष रिकॉर्ड करने के लिए कह रहे हैं कि जब्त की गई संपत्तियाँ उनके अपने वित्त से खरीदी गई थीं; इस प्रक्रिया को अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार का प्रयोग करने के लिए नहीं देखना चाहिए।

31. परिणामस्वरूप, सभी अपीलें खारिज की जाती हैं।

निधि जैन **अपीलें खारिज की गईं।**

***यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।**